NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-05-2025

विषय सूची

सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) नियम, 2025 अधिसूचित किए

लोकसभा में उपसभापति का महत्त्व

अनुभवात्मक शिक्षा

विगत वर्ष गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई

ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025

आगामी पाँच वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5°C को पार कर जाने की संभावना: WMO

संक्षिप्त समाचार

7 समिट्स

अपना डिजीपिन जानें और 'अपना पिन कोड जानें' वेब पोर्टल

खसरे के टीके से विश्व भर में '9 करोड़ मृत्यु' रोकी गईं

संशोधित ब्याज अनुदान योजना(MISS)

कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक(IIP)

इलेक्ट्रिक हंसा (E-Hansa)

ढोल (Dholes)

सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) नियम, 2025 अधिसूचित किए

समाचार में

- रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल और अनुशासन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (ISO) अधिनियम, 2023 के तहत आता है।

पृष्ठभूमि

- ISO अधिनियम, 2023 को संयुक्त रक्षा संरचनाओं जैसे कि संयुक्त कमांड और इंटर-सर्विस प्रतिष्ठानों के सुचारू संचालन को सक्षम करने के लिए लागू किया गया था।
- नव-नोटिफाइड नियम, जो 27 मई 2025 से प्रभावी हैं, इस अधिनियम को लागू करते हैं और इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अन्दर कमांड एवं अनुशासनात्मक शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं।

नियमों के उद्देश्य

- **संयुक्त कमांड को बढ़ावा देना**: संयुक्त सेवाओं के कमांड में सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- **तेजी से अनुशासनात्मक कार्रवाई**: मामलों का त्वरित निपटान करना और प्रक्रियात्मक दोहराव से बचना।
- **संयुक्तता को सुदृढ़ करना**: कानूनी और प्रशासनिक समरसता के माध्यम से सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच परस्पर संचालन क्षमता विकसित करना।

ISO अधिनियम, 2023 – संरचनात्मक प्रावधान

- **ISO का गठन**: केंद्र सरकार को कम से कम दो सेवाओं के कर्मियों से गठित संयुक्त कमांड जैसे ISO बनाने का अधिकार है।
- **पर्यवेक्षण**: समग्र अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोकहित में निर्देश जारी कर सकती है।
- **कमांडिंग ऑफिसर (CO)**: यह अधिनियम किसी भी ISO ढाँचे के तहत किसी इकाई, जहाज या प्रतिष्ठान का नेतृत्व करने के लिए CO प्रदान करता है।

ISO नियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **कमांडरों को सशक्त बनाना**: संयुक्त सेवाओं के कमांड (JSC) के कमांडर-इन-चीफ (CiC), इंटर-सर्विसेज प्रतिष्ठानों के ऑफिसर-इन-कमांड (OiC) और इंटर-सर्विसेज यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर (CO) को सभी तैनात या संलग्न कर्मियों पर पूर्ण अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, चाहे उनकी मूल सेवा कोई भी हो।
- **सेवा अधिनियमों की निरंतरता**: अधिकार सौंपे जाने के बावजूद, मूल सेवा नियम (आर्मी अधिनियम, नेवी अधिनियम, एयरफोर्स अधिनियम) अभी भी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जिससे उनकी सेवा की पहचान बनी रहेगी।
- **शेष शक्तियाँ**: इन नियमों या अधिनियम में स्पष्ट रूप से शामिल न होने वाले किसी भी मामले को केंद्रीय सरकार के पास समाधान के लिए भेजा जाएगा।
- **कमांड की शृंखला**: यदि CiC, OiC, या CO अनुपस्थित हैं या अवकाश पर हैं, तो आधिकारिक रूप से एक प्रतिस्थापन नामित किया जाएगा। आपातकालीन स्थितियों में, उच्चतम संरचनाएँ औपचारिक अधिसूचना तक अंतरिम अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **सेवा संस्कृति के टकराव**: तीनों सेनाओं की कमांड संस्कृति के एकीकरण में आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- **द्वंद्वात्मक अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता**: ISO प्राधिकरण और मूल सेवा की कमांड शृंखला के बीच संभावित टकराव हो सकता है।

- **कानूनी व्याख्या संबंधी विवाद**: सेवा कर्मियों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों के कारण अनुशासनात्मक मामलों में जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जब तक कि उन्हें सामंजस्यपूर्ण नहीं किया जाता।

Source: TH

लोकसभा में उपसभापति का महत्त्व

संदर्भ

- उपाध्यक्ष का पद विगत छह वर्षों से रिक्त पड़ा है, जिससे संवैधानिक अनुपालन और लोकतांत्रिक स्थिरता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

लोकसभा के उपाध्यक्ष

- लोकसभा के उपाध्यक्ष भारत की संसद के निम्न सदन – लोकसभा के द्वितीय प्रधान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
- अनुच्छेद 95(1) के अनुसार, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो उपाध्यक्ष उसकी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं।
- जब अध्यक्ष सदन की बैठक में अनुपस्थित रहते हैं, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- यदि अध्यक्ष संयुक्त बैठक में अनुपस्थित रहते हैं, तो उपाध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव

- लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है।
- अनुच्छेद 93 में कहा गया है, **"लोकसभा को यथाशीघ्र दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनना चाहिए।"**
- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 8 के अंतर्गत उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। नियम 8 के अनुसार, **"चुनाव उस तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष निर्धारित करेंगे।"**
- सामान्यतः अध्यक्ष को सत्तारूढ़ दल या गठबंधन से चुना जाता है, जबकि उपाध्यक्ष को विपक्षी दल या गठबंधन से चुना जाता है।
  - हालाँकि, इस परंपरा में कुछ अपवाद भी रहे हैं।
- 1952 से 1969 तक पहले चार उपाध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से थे। 17वीं लोकसभा (2019-24) के पूरे कार्यकाल में कोई उपाध्यक्ष नहीं था।

शक्तियाँ और विशेषाधिकार

- जब उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं (अर्थात लोकसभा या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं), तो वे अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।
- इस अवधि में, उपाध्यक्ष प्रथम अवसर पर मतदान नहीं कर सकते, बल्कि केवल किसी विवाद की स्थिति में निर्णायक मतदान कर सकते हैं।
- जब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह होते हैं।
- इस अवधि में, उपाध्यक्ष सदन में बोल सकते हैं, इसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और किसी प्रश्न पर प्रथम अवसर में मतदान कर सकते हैं।
- उनके पास एक विशेषाधिकार होता है - जब लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।

लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया

- लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा द्वारा प्रभावी बहुमत (अर्थात कुल सदस्यता में से रिक्त सीटों को छोड़कर बहुमत) से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
- उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव केवल अध्यक्ष को 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- जब उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, तो वे बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालाँकि वे उपस्थित रह सकते हैं।

लंबे समय तक रिक्ति की चिंताएँ

- उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति संवैधानिक मानदंडों के उद्देश्य के खिलाफ जाती है और समावेशी एवं बहुलतावादी संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करती है।
- यह सरकार और विपक्ष के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन को कम कर देता है।
- यदि अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं या अक्षम हो जाते हैं, तो विधायी कार्य बाधित हो सकता है, जिससे संस्थागत गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष

- लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद एक संवैधानिक आवश्यकता है, न कि एक राजनीतिक विकल्प।
- इसकी लंबी अवधि की रिक्ति संविधान की भावना का उल्लंघन करती है और लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करती है।
- इस मुद्दे को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है ताकि संस्थागत संतुलन पुनर्स्थापित किया जा सके और लोकसभा को संवैधानिक मूल्यों के अनुसार सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सक्षम किया जा सके।

Source: TH

अनुभवात्मक शिक्षा

संदर्भ

- वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

परिचय

- **अधिगम की प्रकृति और बदलता परिदृश्य**: मनुष्य स्वाभाविक रूप से सीखने वाला प्राणी है, और आज की डिजिटल दुनिया ने जानकारी तक पहुँच को बदल दिया है।
  - चूँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बॉट्स भी अवधारणाओं को सिखाने में सक्षम हैं, यदि पारंपरिक स्कूल केवल विषयवस्तु प्रदान करने तक सीमित रह जाते हैं, तो वे अप्रासंगिक हो सकते हैं।

अनुभवात्मक अधिगम क्या है?

- अनुभवात्मक अधिगम एक ऐसी विधि है जिसमें सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मचिंतन और अनुप्रयोग के माध्यम से होती है।
- डेविड ए. कोलब (David A. Kolb) को इस सिद्धांत को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
- केवल पढ़ने या व्याख्यान सुनने के बजाय, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उन्हें **"करके सीखने"** का अवसर देती हैं।
- इसमें मुख्य ध्यान सीखने की प्रक्रिया पर होता है, न कि केवल उसके परिणाम पर।

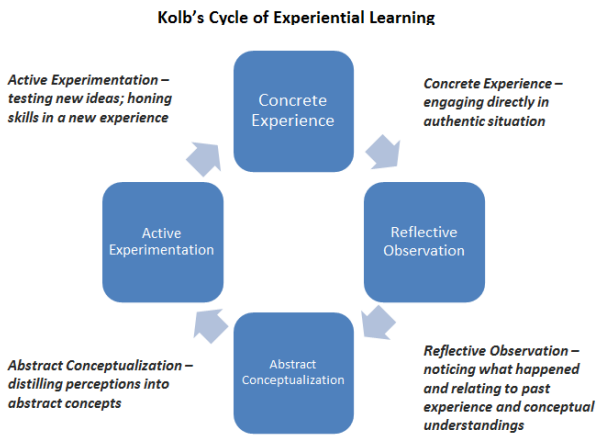

अनुभवात्मक अधिगम के लाभ

- सार्थक चिंतन और समस्या समाधान में सुधार।
- संबंधित विषयों में रुचि और प्रेरणा को बढ़ावा।
- सहयोग और संचार कौशल को प्रोत्साहित करना।
- व्यवहारिक और हस्तांतरणीय कौशल का विकास।

चुनौतियाँ

- अधिक समय, योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- बड़े कक्षाओं में इसे समान रूप से लागू करना कठिन होता है।
- सभी छात्र प्रारंभ में स्व-निर्देशित अधिगम (Self-Directed Learning) के लिए तैयार नहीं हो सकते।

भारत में शिक्षा सुधार की आवश्यकता

- स्कूलों को आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षकों की कमी और असमान पहुँच की समस्या से जूझना पड़ता है, विशेष रूप से ग्रामीण और संसाधन-विहीन क्षेत्रों में।
- वर्तमान प्रणाली अत्यधिक परीक्षा-केंद्रित है और स्मरणशक्ति को बढ़ावा देती है, जिससे आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मकता सीमित होती है।
- मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता (Neuroplasticity) यह सिद्ध करती है कि अलग-अलग अनुभवों के माध्यम से मस्तिष्क समय के साथ सीखने और विकसित करने में सक्षम होता है।

विश्व में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल

- **फिनलैंड**: छात्रों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने और शैक्षणिक दबाव कम करने के लिए प्रसिद्ध। प्रारंभिक वर्षों में खेल-आधारित शिक्षण और आलोचनात्मक सोच पर बल देता है।
- **सिंगापुर**: उच्च मानक और कठोर परिणाम।
  - गणित, पढ़ाई, और विज्ञान में **Programme for International Student Assessment (PISA)** रैंकिंग में विश्व-स्तरीय प्रदर्शन।
  - सावधानीपूर्वक संरचित पाठ्यक्रम।
  - शिक्षकों के विकास में बड़ा निवेश।
- **जापान**: अनुशासन और स्थिरता।
  - शिक्षा और सम्मान को लेकर मजबूत सांस्कृतिक मूल्य।
  - समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम।
  - चरित्र निर्माण और जिम्मेदारी पर जोर (जैसे छात्र स्वयं अपनी कक्षा साफ करते हैं)।
  - मजबूत कार्य नैतिकता और नैतिक विकास।

निष्कर्ष

- भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ गहरी हैं, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है।
- इन्हें संबोधित करने के लिए **सरकारी नीतियाँ, सामुदायिक भागीदारी, शिक्षकों को सशक्त करना और तकनीकी नवाचार आवश्यक हैं।**
- समावेशी, अनुकूलनशील और शिक्षार्थी-केंद्रित सुधारों में निवेश करके, भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित कर सकता है जो अपने नागरिकों को तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके।

Source: TH

विगत वर्ष गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई

समाचार में

- राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) द्वारा 2022–23 और 2023–24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में गरीबी में तेजी से गिरावट आई है और असमानता में मामूली कमी आई है।

गरीबी क्या है?

- गरीबी एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।
- इसकी परिभाषा और माप विभिन्न देशों में अलग-अलग होती है।
- भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है, जो एक सीमा आय स्तर को दर्शाती है।
- जिन परिवारों की खपत इस स्तर से कम होती है, उन्हें गरीब माना जाता है।
- गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय स्तर दर्शाती है जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, और यह विभिन्न देशों में उनकी समग्र आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है।

भारत में गरीबी का मापन

- भारत में गरीबी का आकलन दशकों में विकसित हुआ है। 1971 में **वी. एन. दांडेकर और एन. राठ** ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) डेटा के आधार पर **प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2,250 कैलोरी** की खपत को गरीबी रेखा मानते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **₹15** और शहरी क्षेत्रों के लिए **₹22.5** निर्धारित किया।

- 1979 में **वाई. के. अलघ टास्क फोर्स** ने इसे **ग्रामीण (2,400 कैलोरी) और शहरी (2,100 कैलोरी)** की आवश्यकताओं पर आधारित किया, जो 1990 तक आधिकारिक तरीका बना रहा।
- 1993 में **लक्षद्वाला समिति** ने क्षेत्रीय मूल्य अंतर को ध्यान में रखते हुए राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं को प्रस्तुत किया, लेकिन इसे कैलोरी मानकों से भटकने के कारण आलोचना मिली।
- 2009 में **तेन्दुलकर समिति** ने गरीबी आकलन में बड़े बदलाव सुझाए, जिसमें **कैलोरी आधारित निर्धारण से पोषण परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान उपभोक्ता टोकरी अपनाना, मूल्य समायोजन** और **स्वास्थ्य व शिक्षा व्यय को गरीबी आकलन में शामिल करना** था।
  - इस पद्धति के अनुसार, 2009-10 में गरीबी रेखा **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹673 प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹860 प्रति माह** तय की गई थी।
  - जो व्यक्ति इससे कम व्यय करता था, उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था।
  - 2011-12 में **तेन्दुलकर पद्धति** के अनुसार गरीबी दर **21.9%** थी।
- बाद में, **रंगराजन समिति (2012–14)** ने अलग-अलग ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं को पुनर्स्थापित किया, जिससे गरीबी सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया।

क्या आप जानते हैं?

- **विश्व बैंक ने सितंबर 2022 में वैश्विक गरीबी रेखा को $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** कर दिया, जो **2017 की गरीबी रेखा $1.90** से अधिक है।

भारत में गरीबी की प्रवृत्ति

- कुल गरीबी दर **2011–12 में 29.5% से घटकर 2022–23 में 9.5%** और **2023–24 में 4.9%** रह गई।
- यह प्रवृत्ति **GDP वृद्धि और सामान्य मुद्रास्फीति में गिरावट** से मेल खाती है, हालाँकि **खाद्य मुद्रास्फीति** में हल्की वृद्धि देखी गई।
- कल्याणकारी योजनाएँ यथावत बनी रहीं, जिससे संकेत मिलता है कि **आर्थिक विकास हालिया गरीबी में कमी का मुख्य कारक हो सकता है।**
- **विश्व बैंक ने हाल ही में 100 से अधिक विकासशील देशों के लिए "Poverty & Equity Brief" जारी किया**, जिसमें **भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3%** रह गई।
  - आंकड़ों के अनुसार, **अधिकांश गरीब गरीबी रेखा के ठीक नीचे केंद्रित हैं**, जबकि **कई गैर-गरीब थोड़े ही ऊपर हैं**, जिससे यह संकेत मिलता है कि **भारत में गरीबी गहरे स्तर तक जड़ नहीं जमा रही है।**
  - **125% गरीबी रेखा तक बढ़ाने पर भी गिरावट महत्त्वपूर्ण बनी रहती है।**
  - **असमानता, जिसे गिनी गुणांक (Gini coefficient) द्वारा मापा जाता है, 2011-12 में 0.310 से घटकर 2023-24 में 0.253** हो गई, विशेषतः **2022-23 और 2023-24 के बीच यह गिरावट अधिक तीव्र रही।**

सरकारी कदम

- भारत सरकार ने **जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और गरीबी को कई रूपों में कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं।**
- सरकार द्वारा **रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए लागू प्रमुख कार्यक्रम – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)** हैं।
- **"पोषण अभियान" और "एनीमिया मुक्त भारत"** जैसी प्रमुख पहलें **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच** में सुधार कर रही हैं। सरकार **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम"** के अंतर्गत **विश्व की सबसे बड़ी खाद्य**

सुरक्षा योजनाओं में से एक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) भी संचालित करती है।

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** के अंतर्गत **पाँच वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण जारी रखने का निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।**
- **स्वास्थ्य योजनाएँ, उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन वितरण, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत् कवरेज, स्वच्छ भारत अभियान, और जल जीवन मिशन** जैसी पहल **रहने की स्थिति में व्यापक सुधार** ला रही हैं।
- इसके अतिरिक्त, **प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना** जैसी प्रमुख योजनाएँ **वित्तीय समावेशन और गरीबों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं**

Source :IE

ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025

संदर्भ

- 2025 ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स को CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) में काम करने वाली चार प्रयोगात्मक सहयोग टीमों—ATLAS, CMS, ALICE और LHCb को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।
- इन चार टीमों ने **हिग्स बोसॉन** का अध्ययन किया, जिसे **इलेक्ट्रॉनों, फोटॉनों और न्यूट्रिनो** की तरह मौलिक कण माना जाता है।

ब्रेकथ्रू प्राइज क्या हैं?

- ब्रेकथ्रू प्राइज की स्थापना **सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान, मार्क जकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर, और ऐनी वोज्सिकी** द्वारा की गई थी।
- इन्हें प्रायः**"विज्ञान के ऑस्कर"** के रूप में संदर्भित किया जाता है, और ये **जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित** में अग्रणी उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं।
- **उद्देश्य**: वैज्ञानिकों को समाज के नायकों के रूप में मान्यता देना, युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना, और **"सभी के लाभ के लिए विज्ञान"** को बढ़ावा देना।

वैश्विक सहयोग में भारत की भूमिका

- भारतीय वैज्ञानिकों ने **ALICE (A Large Ion Collider Experiment)** और **CMS (Compact Muon Solenoid)** प्रयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **ALICE में योगदान**: यह **क्वार्क-ग्लूऑन प्लाज्मा (QGP)** का अध्ययन करने पर केंद्रित है, जो **बिग बैंग के ठीक बाद उपस्थित पदार्थ की अवस्था** माना जाता है।
- **CMS में योगदान**: भारतीय संस्थानों ने **डिटेक्टर विकास, सॉफ्टवेयर उपकरण और डेटा विश्लेषण** में योगदान दिया, जो **हिग्स बोसॉन की खोज में महत्त्वपूर्ण** था।

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)

- LHC **विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक** है, जो **उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन और भारी-आयन टकराव** के माध्यम से **पदार्थ की सबसे छोटी संरचनाओं** की खोज करता है।
  - यह **CERN में स्थित 27 किलोमीटर लंबी सुरंग जैसी संरचना** है।
- **CERN: यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन** CERN की स्थापना **1954 में जिनेवा (फ्रांस-स्विट्जरलैंड सीमा)** पर की गई थी।
- **भारत–CERN साझेदारी**
  - **1991**: परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने CERN के साथ प्रथम सहयोग समझौता किया।
  - **2002**: भारत को CERN में पर्यवेक्षक (Observer) का दर्जा दिया गया।
  - **2009**: **डिटेक्टर तकनीक, कंप्यूटिंग, मानव संसाधन प्रशिक्षण और संयुक्त अनुसंधान** में सहयोग के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

- **2017**: भारत **CERN का सहयोगी सदस्य (Associate Member State)** बना।

Source: PIB

आगामी पाँच वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5°C को पार कर जाने की संभावना: WMO

संदर्भ

- विश्व मौसम संगठन (WMO) ने 'ग्लोबल एनुअल टू डेकाडल क्लाइमेट अपडेट (2025-2029)' जारी किया है।

मुख्य तापमान पूर्वानुमान

- **2024:** 2024 न केवल रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष रहा बल्कि यह 1850-1900 के आधार रेखा से 1.5°C अधिक तापमान पार करने वाला पहला वर्ष भी बना।
- **2025-2029:** 70% संभावना है कि इस अवधि के दौरान औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C अधिक रहेगा।
  - आगामी 5 वर्षों में 80% संभावना कि कम से कम एक वर्ष 2024 के तापमान को पार करेगा।
  - 86% संभावना कि कम से कम एक वर्ष 1.5°C सीमा पार करेगा।
  - औसत वैश्विक तापमान 1850-1900 के औसत की तुलना में 1.2°C से 1.9°C अधिक होने का अनुमान।
  - 2025-2029 की मई-सितंबर अवधि में औसत से अधिक वर्षा की संभावना।
  - 1% संभावना कि अगले 5 वर्षों में कम से कम एक वर्ष 2°C से अधिक गर्मी पार करेगा।

क्षेत्रीय जलवायु परिदृश्य

- **दक्षिण एशिया:** 2023 को छोड़कर अधिक वर्षा वाले वर्ष देखे गए हैं, और यह प्रवृत्ति 2025 से 2029 तक जारी रहने की संभावना है, हालाँकि कुछ मौसम शुष्क रह सकते हैं।
- **आर्कटिक:** सर्दियों में 2.4°C तापमान वृद्धि का अनुमान—आगामी पाँच वर्षों में वैश्विक औसत से 3.5 गुना अधिक।
  - समुद्री बर्फ और अधिक सिकुड़ेगी, विशेष रूप से बेरेंट्स सागर, बेरिंग सागर और ओखोट्स्क सागर में।

क्षेत्रीय विसंगतियाँ (2025-2029)

- **अधिक वर्षा:** साहेल, उत्तरी यूरोप, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया।
- **कम वर्षा:** अमेज़न क्षेत्र।

भारत

- भारत ने विगत 5 वर्षों में 4 बार सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त की।
- IMD (भारतीय मौसम विभाग) ने 2025 में सामान्य से अधिक मानसून वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है।

पेरिस समझौता

- यह जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 2015 में COP21 (UNFCCC) में अपनाया गया था।
- इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से कम रखना और 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- 1.5°C सीमा एक लक्ष्य है, कोई कानूनी सीमा नहीं।
- स्थायी उल्लंघन का अर्थ है 20-30 वर्षों तक दीर्घकालिक तापमान वृद्धि, न कि केवल एक वर्ष का आँकड़ा।
- पेरिस समझौता देशों द्वारा निर्धारित योगदान (NDCs) पर बल देता है और सभी देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करता है।
- प्रत्येक पांच वर्षों में NDCs की समीक्षा और अद्यतन करना अनिवार्य होता है ताकि जलवायु लक्ष्यों की महत्वाकांक्षा बढ़ाई जा सके।
- UNFCCC के 195 सदस्य देशों में से 180 को अभी भी 2031-35 के लिए अगली NDCs प्रस्तुत करनी हैं, जो COP30 से पूर्व पूरी होनी चाहिए।

विश्व मौसम संगठन (WMO)

- यह 193 सदस्य देशों और क्षेत्रों के साथ एक सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी।

- यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है जो मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान के लिए कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।
- इसकी सर्वोच्च संस्था विश्व मौसम कांग्रेस है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

7 समिट्स

संदर्भ

- हैदराबाद के किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकंती 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय और विश्व के दूसरे सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं।

परिचय

- 7 समिट्स को प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी के रूप में परिभाषित किया जाता है, और यह वैश्विक पर्वतारोहण में सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में से एक मानी जाती है।
- इन सात पर्वत चोटियों में शामिल हैं:
  - माउंट एवरेस्ट (एशिया)
  - माउंट किलिमंजारो (अफ्रीका)
  - माउंट एल्ब्रुस (यूरोप)
  - माउंट अकोंकागुआ (दक्षिण अमेरिका)
  - माउंट कोसिउज़्को (ऑस्ट्रेलिया)
  - माउंट विन्सन (अंटार्कटिका)
  - माउंट डेनाली (उत्तर अमेरिका)
- कुछ लोग 'महाद्वीप' को अलग तरह से परिभाषित करते हैं, जिससे एक वैकल्पिक 'सातवीं चोटी' बनती है:
  - **ऑस्ट्रेलिया: माउंट कोसिउज़्को या**
  - **ऑस्ट्रेलासिया: कार्स्टेन्ज पिरामिड**
- **माउंट एवरेस्ट (एशिया) सातों में सबसे ऊँचा है, जबकि माउंट कोसिउज़्को (ऑस्ट्रेलिया) सबसे छोटा है।**
  - **ऊँचाई के घटते क्रम में 7 समिट्स**
    1. माउंट एवरेस्ट
    2. माउंट अकोंकागुआ
    3. माउंट डेनाली
    4. माउंट किलिमंजारो
    5. माउंट एल्ब्रुस
    6. विन्सन मैसिफ
    7. कार्स्टेन्ज पिरामिड और माउंट कोसिउज़्को

क्या आप जानते हैं?

- जॉर्डन रोमेरो, एक अमेरिकी पर्वतारोही, दिसंबर 2011 में 15 वर्ष, 5 महीने और 12 दिन की उम्र में विन्सन मैसिफ पर चढ़ाई पूरी करने के बाद 7 समिट्स को पूरा करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बने।
- उन्होंने जॉर्ज एटकिन्सन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
- प्रथम व्यक्ति जिसने 7 समिट्स पूरा किया, वह 1985 में अमेरिकी व्यवसायी और पर्वतारोही रिचर्ड बैस थे।

Source: TH

अपना डिजीपिन जानें और 'अपना पिन कोड जानें' वेब पोर्टल

संदर्भ

- डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने **'Know Your DIGIPIN'** और **'Know Your PIN Code'** नामक दो परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं।

परिचय

- ये प्लेटफॉर्म **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022** के अनुरूप लॉन्च किए गए हैं, जिसका उद्देश्य **डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत भू-स्थानिक अवसंरचना विकसित करना** है।

DIGIPIN (डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर)

- यह एक **ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल, जियो-कोडेड, ग्रिड-आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम** है, जिसे **डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और NRSC, ISRO** के सहयोग से विकसित किया है।
  - यह **Address-as-a-Service (AaaS)** प्रदान करता है—**पता डेटा प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं का एक समूह**, जो **उपयोगकर्ताओं, सरकारी संस्थानों और निजी संगठनों के बीच सुरक्षित और कुशल संपर्क का समर्थन करता है।**
- **'Know Your DIGIPIN' पोर्टल उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाता है:**
- सटीक भौगोलिक स्थान के आधार पर अपना DIGIPIN प्राप्त करने के लिए।
- अक्षांश और देशांतर निर्देशांक इनपुट करके संबंधित DIGIPIN प्राप्त करने या इसके विपरीत प्रक्रिया करने के लिए।
- यह पहल स्थान मानचित्रण को सरल बनाती है, लॉजिस्टिक्स और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाती है, और विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में अंतिम-मील वितरण को सुनिश्चित करती है।
- यह अब सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संस्थानों के लिए उनके कार्यप्रवाह में एकीकृत करने हेतु और उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध है।

Source: PIB

खसरे के टीके से विश्व भर में '9 करोड़ मृत्यु' रोकी गईं

संदर्भ

- खसरा के प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रमों के विकास और विस्तार के कारण वैश्विक मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। खसरा टीके के प्रारंभ होने के बाद से अनुमानित 9 करोड़ (90 मिलियन) लोगों की मौत को रोका जा चुका है।

खसरा

- खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।
- **संक्रमण का तरीका:** यह संक्रमित व्यक्तियों की नाक,मुँह या गले से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है।
- **लक्षण:** संक्रमण के 10–12 दिनों बाद लक्षण प्रकट होते हैं, जिनमें तेज़ बुखार, नाक बहना, लाल आँखें और मुँह के अंदर छोटे सफेद धब्बे शामिल होते हैं।
- **जटिलताएँ:** निमोनिया, मस्तिष्क शोथ (एनसेफलाइटिस), अंधापन और मृत्यु, विशेष रूप से कम पोषण या कमजोर प्रतिरक्षा वाले बच्चों में।

- **रोकथाम:** समुदाय-व्यापी टीकाकरण खसरा को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।
  - जॉन एंडर्स ने 1963 में 'एडमॉनस्टन-B' स्ट्रेन से पहला प्रभावी खसरा टीका विकसित किया था।

Source: TH

संशोधित ब्याज अनुदान योजना(MISS)

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत ब्याज अनुदान (IS) घटक की निरंतरता को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी दी।

परिचय

- MISS एक **केंद्रीय क्षेत्र योजना** है, जिसका उद्देश्य **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना** सुनिश्चित करना है।

योजना के अंतर्गत:

- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ₹3 लाख तक का अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, जिसमें पात्र ऋणदाता संस्थानों को 1.5% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
- ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% तक की प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) मिलती है, जिससे उनकी KCC ऋण पर प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% रह जाती है।
- पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए विशेष रूप से लिए गए ऋणों पर ₹2 लाख तक के लिए ब्याज लाभ लागू होता है।

कृषि ऋण के प्रमुख बिंदु

- KCC के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2014 में ₹4.26 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 तक ₹10.05 लाख करोड़ हो गया।
- कुल कृषि ऋण प्रवाह FY 2013-14 में ₹7.3 लाख करोड़ से बढ़कर FY 2023-24 में ₹25.49 लाख करोड़ हो गया।
- अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए "किसान ऋण पोर्टल (KRP)" जैसे डिजिटल सुधारों से दावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है

Source: PIB

कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

समाचार में

- सरकार ने **विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** में वृद्धि की है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
- विगत वर्ष की तुलना में **नाइजरसीड (₹820 प्रति क्विंटल)** पर सबसे अधिक MSP वृद्धि की सिफारिश की गई है, इसके बाद **रागी (₹596 प्रति क्विंटल), कपास (₹589 प्रति क्विंटल) और तिल (₹579 प्रति क्विंटल)** का स्थान है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- यह वह न्यूनतम दर है जिस पर किसान अपनी फसल सरकार को बेचते हैं।
- MSP किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाता है और आय की सुरक्षा प्रदान करता है।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP), जिसे 1965 में स्थापित किया गया था, MSP निर्धारित करने के लिए कई कारकों पर विचार करता है।
  - MSP पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा लिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

महत्त्वपूर्ण कारक:

- CACP फसल उत्पादन लागत, माँग-आपूर्ति प्रवृत्ति, घरेलू और वैश्विक कीमतें, अंतर-फसल मूल्य संतुलन, और व्यापक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करता है।
- MSP यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ मार्जिन मिले।

- इन लागतों में श्रम, भूमि किराया, बीज, उर्वरक, सिंचाई, मशीनरी का उपयोग, ईंधन, पूँजी पर ब्याज और पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल होता है।

Source :TH

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक(IIP)

समाचार में

- भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल में 2.7% पर आ गई, जो विगत आठ महीनों में सबसे कम रही। इसका मुख्य कारण खनन उत्पादन में गिरावट, उच्च आधार प्रभाव और धीमी बिजली उत्पादन रहा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के बारे में

- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) 1950 से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) संकलित कर रहा है।
- IIP लास्पेयरे के सूत्र का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन को मापता है, जो मुख्य रूप से भौतिक उत्पादन डेटा पर आधारित होता है, हालाँकि कुछ वस्तुएँ जैसे मशीनरी मूल्य शब्दों में रिपोर्ट की जाती हैं और उन्हें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से समायोजित किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय (UNSO) द्वारा अनुशंसित IIP का दायरा खनन, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति को शामिल करता है।
  - हालाँकि, डेटा उपलब्धता की सीमाओं के कारण, भारत में संकलित IIP में निर्माण, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
- आठ प्रमुख उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली—ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के कुल भार का 40.27% योगदान करते हैं।

Source :TH

इलेक्ट्रिक हंसा (E-Hansa)

संदर्भ

- भारत ने इलेक्ट्रिक हंसा (E-Hansa), एक अगली पीढ़ी के दो-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

परिचय

- इलेक्ट्रिक हंसा (E-HANSA) ट्रेनर विमान CSIR-नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) द्वारा विकसित किया गया है।
- E-HANSA HANSA-3 (NG) ट्रेनर विमान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे भारत में पायलट प्रशिक्षण के लिए एक किफायती और स्वदेशी विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है।
- भारत का E-Hansa विमान हरित उड्डयन लक्ष्यों की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा और विमान संचालन में स्वच्छ ऊर्जा ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- यह आयातित विकल्पों की तुलना में काफी कम लागत वाला होने की संभावना है।

Source: PIB

ढोल (Dholes)

समाचार में

- विशाखापत्तनम का इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विश्व ढोल दिवस मना रहा है।

ढोल

- इन्हें एशियाई जंगली कुत्ते (क्यूऑन अल्पाइनस) के नाम से भी जाना जाता है।
- वे दक्षिण-पूर्व एशिया के मूल निवासी कैनिड हैं।
- वे सामान्यतः जंगल में 10-13 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन कैद में 16 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।
- **वितरण:** उनकी वैश्विक जनसंख्या 949 और 2,215 वयस्कों के बीच होने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से भारत और थाईलैंड में पाए जाते हैं।
- **गिरावट में योगदान देने वाले कारक:** आवास की हानि, शिकार में कमी, उत्पीड़न, बीमारी और अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा ने ढोल जनसंख्या को खंडित कर दिया है।
- **संरक्षण स्थिति:** इसे CITES - परिशिष्ट II में शामिल किया गया है
  - ढोल को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Source :TH